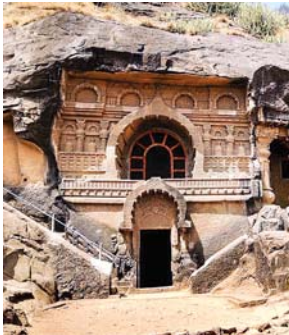


ARBIT



Monks Built South Asia's...

Strategic placement of these monasteries along commercial routes was no accident. Traders frequently stopped here for lodging, security, networking, and financial transactions

Counting Yellow-Breasted Bunting

Bhairavi Brahmani and Ramakrishna Paramahamsa

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के खिलाफ याचिका दर्ज

राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने यह याचिका दर्ज की, क्योंकि राहुल समय से सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाये थे

–रेणु मित्तल–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपना विरोध और तेज कर दिया है।

उन्होंने मध्य दिल्ली की सड़कों पर कर्नाट प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक एक विशाल रैली का नेतृत्व किया। इसे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के बाद, अब तक की सबसे बड़ी भीड़ वाला प्रदर्शन माना जा रहा है।

विपक्षी सांसद कॉनिस्टट्यूशन क्लब में एकत्र हुए और बसों से बाराखंबा रोड पहुंचे। वहां से वे सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना हुए।

विपक्षी नेता अखिलेश यादव, जो आज दोपहर दिल्ली पहुंचे, तेजस्वी यादव और कई अन्य विपक्षी सांसदों के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल हुए।

राहुल गांधी शाम 4:30 बजे की समय-सीमा तक सुप्रीम कोर्ट नहीं

- याचिका दायर करने के लिए इण्डिया ब्लॉक के लगभग सभी सांसद, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि मौजूद थे। सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर एकत्रित होकर, बसों द्वारा बाराखम्भा रोड पहुंचे तथा, वहां से सुप्रीम कोर्ट पैदल गये।

- राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से समय मांगकर मिलने गये थे, पर मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दी कि वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करें, क्योंकि मसला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः वे (मुख्य न्यायाधीश) इस मसले पर उनसे नहीं मिल पायेंगे।

पहुंच सके, इसलिए उनकी ओर से एक वकील ने याचिका दायर की।

“एसआईआर पर रोक लगाओ” (पॉज एस.आई.आर.) शीर्षक वाली 10 सूत्रीय याचिका में कई मांगें की गई हैं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग भी शामिल है।

राहुल ने देशभर के लोगों को, यहां तक कि भाजपा के भी उन लोगों को, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन और मार्च में शामिल

होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि यह “शिवजी की बारात” है और इसमें शामिल होने के लिए सभी का स्वागत है।

उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी के मास्टर

माइंड नहीं हैं। राहुल ने सलाह दी कि उन्हें (ज्ञानेश कुमार) “अप्रवर” (सरकारी गवाह) बन जाना चाहिए, क्योंकि वे मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने नहीं रह सकते और उन्हें पद

छोड़ना ही होगा।

इस मामले में टकराव और तेज हो गया है। जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर तीन अन्य जगहें दी गई हैं, लेकिन वे लुटियंस दिल्ली से काफी दूर हैं।

अब प्रदर्शनकारी कहीं भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 40,000 पुलिसकर्मी मध्य दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों को रोकें हुए हैं।

राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग से जुड़ी याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। यह याचिका तब दायर की गई, जब मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें याचिका दायर करनी चाहिए।

राहुल गांधी का रुख स्पष्ट है। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यह आखिरी दम तक की लड़ाई है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ना ही होगा।

‘ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिये’

– जाल खंबाता –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास सरकारी गवाह बनने के अलावा

- राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए ज्ञानेश कुमार के संबंध में कहा, “उन्होंने एक अपराध किया है, परन्तु वे मुख्य अपराधी नहीं हैं”

कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि “उन्होंने अपराध किया है।” लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस मार्च का उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कोई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पंजाब मुख्यमंत्री के निजी सचिव की जांच करें’

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सीबीआई) और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के

- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सी.बी.आई. जांच के आदेश को स्वीकृति दी।

कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तारी सहित, कोई भी सख्त कार्रवाई करने से रोक दिया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुरेंद्रा और न्यायमूर्ति पी. बी. चराले की पीठ ने दोनों केन्द्रीय एजेंसियों और अधिकता निखिल सराफ को नोटिस जारी किया। सराफ की याचिका पर ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई को आरोपों के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाए।

यह अंतरिम राहत पंजाब सरकार की उस याचिका पर दी गई, जिसमें हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु के मु.मंत्री बड़ी जल्दी सीख गये, दो महारथियों, प्रतिद्वंदियों के बीच कैसे जिया जाता है

वे तमिलनाडु में सैक्युलर, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी, कांग्रेस व अन्य छोटी -छोटी पार्टियों के समर्थन से सत्ता में है

–श्रीनंद झा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे अभियान और उस पर हो रही तीखी बयानबाजी के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में भाजपा को निशाना बनाते हुए एक और राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार तमिल भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर “पूरी ताकत से हमला” कर रही है।

“उत्तर-दक्षिण विभाजन” पर छिड़े इस नए विवाद ने स्वाभाविक रूप से भाजपा को नाराज कर दिया है। भाजपा ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वे देश में विभाजन बढ़ाने के इरादे से “जानबूझकर भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं।”

- दूसरी ओर, केन्द्र की मोदी सरकार से भी “मधुर” संबंध रखना चाहते हैं, केन्द्र फण्ड, प्रोजेक्ट्स व प्रशासनिक स्थिरता के लिये।

- विजय बड़ी सोच-समझ के बाद डी.एम.के. के मुख्यमंत्री स्टालिन की भांति केन्द्र के साथ प्रतिद्वंदी की भूमिका नहीं अपनाना चाहते।

- विजय तमिल आइडेंटिटी व व्यवहारिक प्रशासन के बीच संतुलन बिठाने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ जुबानी

जंग में उलझी हुई हैं, तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दोनों तरफ तालमेल बिठाने की राजनीति करते दिख रहे हैं। शनिवार को उनकी राहुल गांधी के साथ कॉफी पीते हुए तत्क्षीर सामने आईं। अगले दिन वे नरेंद्र मोदी के साथ मंदिर गए और उन्होंने चेन्नई मेट्रो के नए

शुरू किए गए हिस्से में मोदी के साथ यात्रा भी की।

संतुलन बनाने की इस कोशिश में विजय जाहिर तौर पर व्यावहारिक राजनीति अपना रहे हैं। वे कांग्रेस और छोटी पार्टियों के साथ “सैक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस” बनाए हुए हैं, जो उनकी अल्पमत

रंघावा और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा तक, कई प्रमुख नेता शामिल हुए। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यक्रम का संचालन किया।

वडिंग ने अपने बारे में तृतीय पुरुष (थर्ड पर्सन) के तौर पर जिक्र करते हुए कहा, “निस्संदेह, कई लोगों ने राजा वडिंग का विरोध किया और शायद भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।”

छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद

सुकमा, 12 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों द्वारा लगातार चलाये जा रहे सर्वे अभियान के तहत, सोमवार को किस्टाराम थाना क्षेत्र के ग्राम पालाचलमा के दुर्गम

पहाड़ी-जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए नक्सली डम्प का पता चला। सुरक्षाबलों ने डम्प से कुल 13 हथियार, 46 जिंदा राउंड,

बीजीएल लॉन्चर, 208 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर तथा विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली उपयोग की वस्तुएँ बरामद की गई हैं।

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर ने आज इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से दुर्गम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओम माथुर केरलम के राज्यपाल बने

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरलम का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि राजेन्द्र विश्वनाथ अलैंकर को केरलम से ट्रांसफर कर तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। आदेश के अनुसार, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उन्होंने हिंदी शोपे जाने की आशंका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तीन भाषा फार्मूले, शिक्षा के लिए फंड न देने, तमिल मीडियम वाले छात्रों पर नीट का असर, विश्वविद्यालयों में खाली पदों, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओम माथुर केरलम के राज्यपाल बने

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के

- राष्ट्रपति ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति व फेरबदल की घोषणा की।

अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरलम का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि राजेन्द्र विश्वनाथ अलैंकर को केरलम से ट्रांसफर कर तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। आदेश के अनुसार, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक और डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)